इस दिशा में किस प्रकार के नवीन विकासों की योजना बनाई जा रही है; और

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी० एस० एल० वी०) अन्तरिक्ष में कब छोड़ा जाएगा और इससे क्या सेवाएं ली जाएंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) :

(क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित और 1975 तथा 1983 के बीच छोड़े गए परीक्षणात्मक उपग्रह आर्यभट भास्कर-I और भास्कर-II, रोहिणी (आर० एस० डी० 2) और एम्पल कक्षा में हैं। इन उपग्रहों ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अब वे पूर्णतया निष्क्रय हैं। उनमें से कुछ का कभी-कभी अनुवर्तन किया जाता है और उनसे दूरमिति संकेत प्राप्त होते हैं।

विदेश से प्राप्त दो उपग्रह, इन्सैट-I ए० और 1बी०, जिनको क्रमश: 1982 और 1983 में छोड़ा गया था, कक्षा में हैं। इनमें से केवल इन्सैट-1बी ही प्रचालनात्मक उपग्रह है; इन्सैट-1ए प्रमोचन के तुरन्त बाद ही असफल हो गया था। इन्सैट-1बी का उपयोग निम्नलिखित सेवाओं के लिए किया जा रहा है :-

-रेडियो और टी०वी० संचारजाल

-सीधे दूरदर्शन प्रसारण

-दूर संचार

-मौसमविज्ञानीय भू-पर्यवेक्षण; और आपदा चेतावनी

इन्सैट-1 श्रृंखला का एक अन्य उपग्रह, इन्सैट-1सी, जो दो इन्सैट उपग्रहों के संरुपण को पूर्ण करेगा और इन्सैट-1बी के लिए कक्षा में एक अतिरिक्त सक्रिय उपग्रह होगा तथा इसकी सेवाओं का विस्तार करेगा, को 1988 के आरम्भ में जोड़ जाने की योजना है। उपग्रहों की इन्सैट-I श्रृंखला को द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी रूप से विकसित इन्सैट II अंतरिक्षयानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दो इन्सैट-II जांच अंतरिक्षयानों में से प्रथम अब विकासाधीन है और इसका प्रमोचन-अभियान 1989 के अंत के लिए निर्धारित है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इस समय विकासाधीन अन्य उपग्रह निम्नलिखित है :-

(1) प्रौद्योगिकीय, वैज्ञानिकी और उपयोग मिशनों के लिए विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस) ; इसका प्रथम उपग्रस अक्टूबर, 1986 में छोड़े जाने की योजना है।

(2) देश में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध में सुदूर संवेदन उपयोगों के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आई०आर० एस० उपग्रह; इसका प्रथम अर्थ-प्रचालनात्मक उपग्रह 1987 में छोड़े जाने की योजना है।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल वी०) का प्रथम प्रमोचन 1989-90 के लिए निर्धारित है। पी० एस० एल० वी० परियोजना का उद्देश्य 1000 कि० ग्रा० श्रेणी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम स्वदेशी प्रचालनात्मक प्रमोचक राकेटों का विकास करना है।

Women offenders

491. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of womenoff enders in detention in the country in different States, State-wise; and

(b) what steps Government have taken in evolving a more humane policy towards women offenders in detention light of various judgement of the Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI GHULAM NABI AZAD) (a) The available information is given in the attached statement (*see below*).

(b) The Code of Criminal Procedure, 1973 provides adequate safeguards for ensuring dignity and decency of women in custody. Detailed instructions have been issued to State Governments and Union territory Administrations regarding treatment of women offenders in matters of search, arrest, lock up police remand and examination of women as witnesses, utilising the Services of women police and in-service and orientation training of police with emphasis on status of women. Further in order to ensure that women kept in jails are not exposed to exploitation, the Centre is providing funds to the States for the purpose of constructing exclusive separate jails/annexe for women prisoners. These jails/annexes are required to be under the supervision of women staff.

Statement

Women Prisoners in Jails in India

1.	Andhra Pradesh	115	As on 30-6-1985
2.	Assam	205	—do—
3.	Bihar	283	As on 31-12-1983
4.	Gujarat	89	—do—
5.	Haryana	48	—do—
6.	Himachal Pradesh	6	—do—
7.	Jammu & Kashmir	15	—do—
8.	Karnataka	79	—do—
9.	Kerala	119	—do—
10.	Madhya Pradesh	288	—do—
11.	Maharastra	252	—do—
12.	Manipur	27	—do—
13.	Meghalaya	41	—do—
14.	Nagaland	32	—do—
15.	Orrisa	103	—do—
16.	Punjab	173	—do—
17.	Rajasthan	96	—do—
18.	Sikkim	—	do
19.	Tamil Nadu	536	—do—

20.	Tripura	334	As on 31-12-1983
21.	Uttar Pradesh	200	As on 30-6-1984
22.	West Bengal	967	As on 30-6-1985
23.	A & N Islands	1	As on 31-12-1985
24.	Arunachal Pradesh	3	—do—
25.	Chandigarh	5	—do—
26	D & N Haveli	—	—do—
27.	Delhi	44	As on 31-12-1984
28.	Goa, Daman & Diu	5	As on 31-12-1985.
29.	Lakshadweep	—	—do—
30.	Mizoram	16	—do—
31.	Pondicherry.	22	—do—

492. [*Transferred to the 30th July,*

Plan Allocations for Orissa

493. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the Central plan allocations under different heads to Orissa for the year 1986-87;

(b) whether the specific amounts of such allocations made by the Central Government have been included in the State's budget for 1986 under the same head or department earmarked by the Planning Commission; and

(c) what is the amount of plan allocation by the Planning Commission for the year 1986-87 for the Department of Power of Orissa and what is the amount included in the budget of Orissa for that department of 1986-87?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) to (c) A statement is enclosed.

Statement

Sector	Outlays of the state of Orissa for Annual Plan 86-87 as approved by the Planning Commission	Outlays as budgeted by the state Govt. for 1986-87	Variations in column 3 Over column (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Agriculture & Allied Services.	5512	5713	(+) 201